फिसलन भरी ढलान : भारत की ऊर्जा जरूरतों पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

17 अक्टूबर, 2018

द हिन्दू

''भारत को अपनी एनर्जी बास्केट को और अधिक सक्रिय रूप से विविधता प्रदान करना होगा।''

भारत की आर्थिक तकदीर तेल की कीमतों में हो रहे तेजी से उतार-चढ़ाव से जुड़ी रहती आई है। सोमवार को नई दिल्ली में प्रमुख तेल मंत्रियों की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल उत्पादन करने वाले देशों से ऊर्जा की लागत को कम करने के लिए आग्रह किया ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को रिकवरी की दिशा में अपने रास्ते में मदद मिल सके।

श्री मोदी ने डॉलर की मजबूती के चलते तेल आयात करने वाले देशों पर बोझ को कम करने के लिए तेल के भुगतान के लिए अमेरिकी डॉलर के बदले रुपए के आंशिक उपयोग की मांग करने के लिए भुगतान शर्तों की समीक्षा भी मांगी।

आयात के जरिए 80% से अधिक तेल की मांग को पूरा किया जा रहा है, भारत के पास स्पष्ट रूप से हिस्सेदारी है क्योंकि पिछले एक साल में तेल की कीमतों में 70% की वृद्धि हुई है।

विशेष रूप से, इसी कार्यक्रम में बोलते हुए, सऊदी अरब ऊर्जा मंत्री खालिद ए अल-फलीह ने जोर देकर कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि में समर्थन सऊदी अरब के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। वैश्विक तेल बाजार में महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्वी आपूर्तिकर्ताओं की अनुपस्थिति को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ये भारत की मदद करने के इच्छुक हैं।

गौरतलब हो कि 5 जनवरी, 2016 को हुई पहली बैठक में प्राकृतिक गैस कीमतों में सुधार के सुझाव दिए गए थे। इसके एक साल से कुछ अधिक समय बाद सरकार ने गहरे समुद्र जैसे कठिन क्षेत्रों जहां अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, के लिए प्राकृतिक गैस के लिए ऊंचे मूल्य की अनुमति दी थी।

अक्टूबर, 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ओएनजीसी और ऑइल इंडिया के उत्पादक तेल और गैस क्षेत्रों में विदेशी और निजी कंपनियों को इक्विटी देने का सुझाव दिया गया था। लेकिन ओएनजीसी के कड़े विरोध के बाद इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

भारत के नीति निर्माताओं को अब कई बाहरी हेडविंडों के बीच अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रूप से चलाने का कठिन कार्य सामना करना पड़ता है।

चालू खाता घाटा 2018-19 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% तक बढ़ गया है और पूरे वर्ष के लिए 3% तक पहुंचने की उम्मीद है। साल की शुरुआत के बाद से रुपया 16% नीचे है, जो कि रिकवरी के किसी भी संकेत को प्रदर्शित नहीं कर रहा है।

इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल की बिक्री में वृद्धि पहले ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है क्योंकि उनकी कीमतें पहले से काफी ऊँची थी। आने वाले तिमाहियों में यह सब दुनिया में तेजी से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

इस परिदृश्य में, घरेलू ईंधन पर लगाए गए करों को मामूली रूप से कटौती करने का निर्णय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की मदद करने के हालात में नहीं है। उपभोक्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय और राज्य करों में भारी कटौती की आवश्यकता है।

तेल की समस्या का एक और दीर्घकालिक समाधान ऊर्जा आपूर्ति के घरेलू स्रोतों में निहित है, इसके साथ ही उपभोक्ताओं को इस ग्रीन विकल्प का चुनाव करने के लिए भी प्रोत्साहित करना होगा। इसके लिए एक मजबूत नीति ढांचे और कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी।

अल्प अवधि में, सरकार इस समाया को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता आधार को और अधिक विविधता प्रदान कर सकती थी। लेकिन इस तरह के विकल्प का चुनाव करने में ईरान के मुद्दे जैसे भू-राजनीतिक जोखिम भी शामिल होते हैं।

चूंकि तेल आयात से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी समय लगेगा, इसलिए यदि वे ये चाहते है कि तेल पर भारत की निर्भरता अच्छा फल प्रदान करे तो नीति निर्माताओं को सिर्फ अगले चुनाव से परे हट कर सोचने के लिए तैयार रहना चाहिए।

GS World टीम...

संबंधित तथ्य

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेल एवं गैस क्षेत्र की वैश्विक और भारतीय कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ उभरते ऊर्जा परिदृश्य पर विचार-विमर्श किया।
- इस बैठक में ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों तथा कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गयी।
- इस तीसरी सालाना बैठक में तेल एवं गैस खोज तथा उत्पादन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने पर भी चर्चा हुई थी।

पृष्ठभूमि

- पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में निजी हिस्सेदारी लगभग स्थिर है, जबकि ईंधन की मांग सालाना पांच से छह फीसद की दर से बढ़ रही है।
- तेल की मांग में से 80 फीसद के लिए भारत आयात पर निर्भर है।
- गैस की जरूरत में से भी आधे से ज्यादा के लिए आयात पर निर्भरता है।
- 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक आयात पर निर्भरता को 10 फीसद घटाकर 67 फीसद करने का लक्ष्य रखा था। वित्त वर्ष 2014-15 में आयात पर निर्भरता 77 फीसद थी।
- तब से आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है।

रुपये में पेमेंट का सुझाव

- दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर OPEC को भारत ने सुझाव दिया है कि वह भारत को अनुमति दे कि वह तेल के दामों का पेमेंट यूरो और डॉलर की जगह रुपये में करे।
- ओपेक भारत की जरूरत का 60 फीसदी तेल सप्लाई करता है।

ऐसे में यदि यह शर्त मंजूर हो जाती है तो रुपये से पेमेंट से भारत की स्थिति बेहतर हो सकती है।

क्या है ईरान मॉडल

- भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर देश ईरान है।
- अमेरिकी पाबंदी लगने के बाद भारत ने उसे रुपये में पेमेंट में ही पेमेंट किया था।
- इसके पीछे का कारण था कि अमेरिका ने तेहरान को अनुमति दे रखी थी।
- ऐसे में इन रुपये से ईरान भारत से दवाइयां और भोजन खरीदता रहा।
- इस तरह से दोनों देश बिजनेस में डॉलर का प्रयोग नहीं करते रहे।
- ईरान का तेल ऐसे में भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद रहा हैं क्योंकि वह 60 दिन के क्रेडिट पर सप्लाई करता रहा है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. तेल की बढ़ती कीमतों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होगा?

1. रुपयें का कमजोर होना
2. नकारात्मक भुगतान संतुलन
3. मुद्रास्फीति
4. मंद आर्थिक संवृद्धि

नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) 1 और 4

(b) 1, 2 और 4

(c) 1, 2 और 3

(d) उपर्युक्त सभी

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. "भारतीय अर्थव्यवस्था ठहराव, मुद्रास्फीति और बढ़ते व्यापार घाटे की एक गाथा बन गयी है।" आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है?

(250 शब्द)

नोट :

16 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) और 2(b) होगा।